SOCIAL SAFETY NETS FOR URBAN INDIA - EMPLOYMENT GUARANTEE PROGRAM AND PUBLIC CANTEENS IN URBAN RAJASTHAN

KRISHNA PRIYA CHORAGUDI

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

2026

Abstract

This thesis studies recent state-led experiments in urban social protection in India, focusing on Rajasthan’s Urban Employment Guarantee Scheme (Indira Gandhi Rozgar Guarantee Yojana (IRGY)) and a public canteen initiative (Indira Rasoi Yojana). Both programs emerged in response to the vulnerabilities exposed during the COVID-19 lockdowns, particularly among low-income informal workers in cities. Through fieldwork in Jaipur and Udaipur, including household surveys, interviews, and administrative data, the thesis examines how these schemes were implemented, who they reached, and what shaped their outcomes. It builds upon the following strands of literature within development economics: public works programs, women’s work and urban social protection. It is found that IRGY enables women’s entry or re-entry into the labour force and provides a suitable wage employment opportunity for many. In a context where female labour force participation rates have historically been very low, IRGY represents a novel intervention in urban employment policy by expanding the pool of working women, not just redistributing work among those already employed. Half of the IRGY participants in the survey (comprising 8% of the total sample of working-age women) joined the workforce for the first time through this program. The wages earned through the program amounted to nearly 10% of their annual household incomes and contributed to the personal savings of nearly half of the workers in the sample, helped one-third fulfil essential needs and reduced indebtedness for almost a quarter. However, the program still needs to overcome several challenges to effectively improve outcomes, including effective self-selection, program implementation, generation of days of work and payment delays. The challenges in implementation also highlight deeper governance issues in urban areas and the complexities of informality. The public canteens in Rajasthan are found to address food insecurity by offering affordable, nutritious meals and ensuring access to all through their universal design, especially for those excluded from targeted welfare schemes and migrants. The One Nation One Ration Card (ONORC) initiative introduced in the Public Distribution System tries to enable portability of ration benefits across states, however, it is found to have low uptake in addition to a fundamental limitation in catering to mobile and migrant urban households. The thesis recognises that programmes like IRGY and Indira Rasoi Yojana represent a shift in how welfare is understood, treating core necessities such as work and food as guaranteed entitlements rather than things people must secure through the market.

सार

यह शोध भारत में शहरी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हाल ही में किये गए कुछ राज्यों के प्रयोगों का अध्ययन करता है, जिसमें राजस्थान की शहरी रोज़गार गारंटी योजना (आईआरजीवाई) और एक सार्वजनिक कैंटीन पहल (इंदिरा रसोई योजना) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों पहलें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उजागर हुई कमज़ोरियों के प्रत्युत्तर के रूप में सामने आईं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के कम आय वाले अनौपचारिक श्रमिकों के बीच। जयपुर और उदयपुर में फील्डवर्क के माध्यम से, जिसमें घरेलू सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रशासनिक डेटा शामिल हैं, यह शोध इस बात की पड़ताल करता है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ, इनसे कौन-कौन लाभान्वित हुए, और किन कारकों ने इनके परिणामों को आकार दिया। यह विकास अर्थशास्त्र के भीतर साहित्य के निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है: सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम, महिलाओं का कार्य और शहरी सामाजिक सुरक्षा। यह पाया गया है कि आईआरजीवाई महिलाओं को श्रम बल में प्रवेश या पुनः प्रवेश करने में सक्षम बनाता है और कई लोगों के लिए उपयुक्त वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ऐसे संदर्भ में, जहाँ महिला श्रम बल भागीदारी दर ऐतिहासिक रूप से कम रही है, आईआरजीवाई शहरी रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, यह पहले से कार्यरत महिलाओं के बीच काम बाँटने के बजाय नई महिलाओं को श्रम बाजार में लाने का प्रयास करता है। सर्वेक्षण में आईआरजीवाई प्रतिभागियों में से आधे (कामकाजी उम्र की महिलाओं के कुल नमूने का 8%) इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार कार्यबल में शामिल हुए। कार्यक्रम से मिली मजदूरी ने श्रमिकों की वार्षिक घरेलू आय में औसतन लगभग 10% का योगदान दिया। इससे नमूने में लगभग आधे श्रमिकों ने व्यक्तिगत बचत बढ़ाई, एक-तिहाई ने आवश्यक जरूरतें पूरी कीं, और करीब एक-चौथाई ने अपनी ऋणग्रस्तता घटाई। हालाँकि, कार्यक्रम के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का समाधान आवश्यक है जैसे प्रभावी स्व-चयन सुनिश्चित करना, कार्यान्वयन में सुधार करना, पर्याप्त कार्यदिवस सृजित करना और भुगतान में देरी को दूर करना। राजस्थान में सार्वजनिक कैंटीन रियायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर, तथा अपने सार्वभौमिक डिज़ाइन के माध्यम से सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करके, खाद्य असुरक्षा को कम करने में प्रभावी साबित हुई हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) पहल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में राशन लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है, हालाँकि, यह पहल गतिशील और प्रवासी शहरी परिवारों की ज़रूरतों को पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाई है, और इसके कार्यान्वयन में भी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आई हैं। यह शोध दिखाता है कि आईआरजीवाई और इंदिरा रसोई योजना जैसे कार्यक्रम कल्याण की परंपरागत धारणा से एक कदम आगे बढ़ते हैं, वे काम और भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतों को बाज़ार से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बजाय गारंटीकृत अधिकार के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं।